

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 275 का उत्तर

कॉकण रेलवे के विलय की स्थिति

275. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सभी हितधारक राज्य सरकारें कॉकण रेलवे के प्रस्तावित विलय के लिए अपने हिस्से को सौंपने पर सहमत हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ख) कॉकण क्षेत्र की जनता को विलय के संबंध में औपचारिक अधिसूचना कब तक मिलने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): कॉकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) में पांच शेयरधारक अर्थात रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, गोवा सरकार और केरल सरकार हैं। केआरसीएल की अवसंरचना 25 साल से अधिक पुरानी हो चुकी है, जिसके लिए दोहरीकरण और सुरंगों के के पुनरुद्धार सहित यातायात की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के बड़े पैमाने पर नवीनीकरण/प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। इसके लिए अधिक पूंजीगत व्यय की आवश्यकता है। पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को पूरा करने के लिए, रेल मंत्रालय ने उपरोक्त सभी शेयरधारक राज्य सरकारों से केआरसीएल में पूंजीगत व्यय के लिए अपने हिस्से के अनुसार अंशदान करने अथवा रेल मंत्रालय के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ने के लिए संपर्क किया है। केवल गोवा राज्य सरकार ने अपने हिस्से को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है।
